

सतना
09 जुलाई 2025
बुधवार



दैनिक

मीडिया ऑडिटर

सतना, रीवा से एक साथ प्रकाशित



मेरी चिंता मत करो...

@ पेज 7

एक देश-एक चुनाव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं-पूर्व सीजेआई

नई दिल्ली। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रबूद्ध ने कहा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। हालांकि, प्रस्तावित बिल में चुनाव आयोग को दी जाने वाली शीर्षकों पर चिन्ह उल्लेख जारी है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि इससे ईसीआई को विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटने की शक्ति मिल सकती है। उन परिस्थितियों को परिभाषित प्रभाव से क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों पर पड़ता असर जस्टिस चंद्रबूद्ध ने कहा कि एक साथ चुनाव करने से बहुत अधिक स्थिति बाली नेशनल पार्टियों के मिल सकती है। उन परिस्थितियों का परिभाषित किया जाना चाहिए। जिनमें ईसीआई इस शक्ति का



इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस चंद्रबूद्ध ने एक देश-एक चुनाव पर बनी संसदीय समिति को अपनी लिखित रुप सौंपी है। कानून मंत्री अर्जुन रम मेवाल ने 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में एक देश-एक चुनाव संसदीय विधायक प्रताप बाबूराव सरनाईक वहां पहुंचे, इससे एमएनएस कार्यकर्ता भड़के और उनका विरोध किया।

इससे पहले मंगलवार सुबह पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा-पालघर प्रमुख अविनाश जाधव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। जाधव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता द्वारा के भावंदर में

मराठी भाषा विवाद-ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में मराठों को लेकर विवाद के बीच ताणे के भावंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने प्रदर्शन किया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और स्थानीय विधायक प्रताप बाबूराव सरनाईक वहां पहुंचे, इससे एमएनएस कार्यकर्ता भड़के और उनका विरोध किया।

इससे पहले मंगलवार सुबह पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा-पालघर प्रमुख अविनाश जाधव समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। जाधव के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता द्वारा के भावंदर में



व्यापरियों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में एक रैली करने जा रहे थे। पुलिस ने इस रैली की परमिशन नहीं दी थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने पुलिस कमिशनर से बात की है, उन्होंने बताया कि रैली के लिए नहीं, बल्कि सभा के लिए अनुमति मांगी गई थी।

भावंदर में ही 1 जुलाई को एक गुजराती दुकानदारों को मराठी में बात न करने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। इसके विरोध में व्यापरियों ने कार्यवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था।

अहमदाबाद प्लेन फ्रैश- 26 दिन बाद आई शुरुआती जांच रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। एयक्रोफ्ट एक्सीटेंड इवेस्टिगेशन व्यारो ने अहमदाबाद विवान हादसे के 26 दिन बाद प्राइमरी जांच रिपोर्ट मंगलवार को केंद्र सरकार को सौंपी प्राइमरी रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तेवर की गई है। इससे पहले 28 जून को केंद्रीय नागरिक उड्योग राज्य मंत्री मुख्यमंत्री मोहन ने बताया था कि विवान हादस की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें सारिंग (सेवोटाइज) की संधारना को भी खंगाला जा रहा है। वहाँ, 3 महीने में विस्तृत जांच रिपोर्ट आ सकती है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एआई 171 टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्पिट की इमारत से टक्करा गई थी। इसमें 270 लोगों को मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और कू. मंडर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है।

पटना में गोपाल खेमका की हत्या बिल्डर ने कराई

पटना (एजेंसी)। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या बिल्डर अशोक साह ने कराई थी। दोनों के बीच कारोबार को लेकर विवाद था। हत्या के लिए अशोक साह ने शूटर उमेश को हत्यार किया था। उमेश ने ही गोपाल खेमका को 4 जूलाई को घर के गेट पर गोली मारी थी। पुलिस ने शूटर के पास से 3 लाख कैश बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि उदयगिरि अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 601 से अशोक साह को गिरफ्तार किया गया। इस प्लैट में बड़ी कुख्यत अशोक सप्राट और बज़बारी का निशानदेती पार पुलिस गण सप्लायर विकास से पूछताछ करने पटना सिटी के मालालायी इलाके में पहुंची थी। इसी दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। एनकाउंटर मंगलवार तड़के 4 बजे हुआ।

केरल हाईकोर्ट से लाइबेरियाई जहाज की जब्ती का आदेश

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को लाइबेरियाई जहाज एमएससी अकीकेट 2 को जब्त करने का आदेश दिया। यह शिप लाइबेरियाई जहाज स्टैट एप्ल्स 3 का सहयोगी था, जो 25 मई को कोचिंच के टट पर डूब गया था। दोनों जहाज एमएससी मेंडिंरेनियन शिपिंग कंपनी के हैं। एमएससी एल्सा 3 डूबने से हुए पर्यावरणीय और आधिक नुकसान पर केरल सरकार ने 9531 कोडोरुपैर के मुआवजे की याचिका लागई थी। साथ ही सहयोगी जहाज के भारत से बाहर जाने की आशंका जाती हुई थी। साथ ही सहयोगी जहाज के भारत से बाहर जाने की आशंका जाती हुई थी।

केरल हाईकोर्ट से लाइबेरियाई जहाज की जब्ती का आदेश

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को लाइबेरियाई जहाज एमएससी अकीकेट 2 को जब्त करने का आदेश दिया। यह शिप लाइबेरियाई जहाज स्टैट एप्ल्स 3 का सहयोगी था, जो 25 मई को कोचिंच के टट पर डूब गया था। दोनों जहाज एमएससी मेंडिंरेनियन शिपिंग कंपनी के हैं। एमएससी एल्सा 3 डूबने से हुए पर्यावरणीय और आधिक नुकसान पर केरल सरकार ने 9531 कोडोरुपैर के मुआवजे की याचिका लागई थी। साथ ही सहयोगी जहाज के भारत से बाहर जाने की आशंका जाती हुई थी। साथ ही सहयोगी जहाज के भारत से बाहर जाने की आशंका जाती हुई थी।

जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी होगी

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी। इसके लिए विशेष बैठकों को आयोलय के अनुसार, जांतीय गिरनी और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी।

नई दिल्ली। देश में 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना और जनगणना पहली बार डिजिटल प्लेटफ

आईएमए ने जीवनसाथी का सम्मान कर अनूठे अंदाज में मनाया डॉक्टर्स डे

'जीवनसंगिनी के समर्पण भाव के बिना चिकित्सा सेवा असंभव'



मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना आईएमए ने जीवनसाथी का सम्मान कर अनूठे अंदाज में मनाया डॉक्टर्स डे इवेंट के दौरान लोकल एसोसिएशन (आईएमए) ने इस बार डॉक्टर्स डे पर नवाचार करते हुए वर्षा डॉक्टर्स की गृहणियों को सम्मानित कर एक ऐतिहासिक पहल की। आईएमए अध्यक्ष डॉ. राकेश अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर्स को अक्सर उनकी चिकित्सा सेवाओं के लिए सम्मान मिलता है, लेकिन उनकी जीवनसंगिनी के समर्पण को

पहचानना भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा, "डॉक्टर्स की व्यस्तता के कारण परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी उनकी पलियों पर होती है। उनके समर्पण के बिना चिकित्सा और डॉ. चांदना अग्रवाल और प्रियंका प्रजापति ने किया।

मरणोजन के लिए डॉ. रेखा पांडे, डॉ. प्रतिभा दुबे, डॉ. सुनीता गुरुता, रंजना गौतम और डॉ. अलोक खन्ना ने सम्मानित किया। डॉ. देवेंद्र सिंह ने कहा कि चिकित्सा सेवा में अग्रवाल को जुड़ाव जरूरी है। सचिव डॉ. अलोक खन्ना ने बताया कि अयोजन का संचालन मुख्य रूप से डॉक्टर्स की जीवनसंगिनीयों - आभा अग्रवाल, संघा गांधी, डॉ.

प्रियंका अग्रवाल, डॉ. त्रेया सराफ, रेली खन्ना, डॉ. प्रियंका जैन, डॉ. रिंश जैन, डॉ. वंदना मर्स्कोले, डॉ. चांदना अग्रवाल और प्रियंका प्रजापति ने किया।

मरणोजन के लिए डॉ. रेखा पांडे, डॉ. प्रतिभा दुबे, डॉ. सुनीता गुरुता, रंजना गौतम और डॉ. अलोक खन्ना ने गैम्स का आयोजन किया। आयोजन के सफल संयोजन में डॉ. संकल्प जैन, डॉ. मुदित जैन, डॉ. संजीव प्रजापति और डॉ. अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सम्मान प्रक्रिया में मधु जायसवाल, कमिस्नर

संचालक नगरीय प्रशासन को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में संतलाल साहने ने उनके नाती के कक्ष की नींव में सुनवाई की। कमिश्नर ने उनके अधिकारियों को जनसुनवाई के आवेदन परों में साधारण दिवस में कार्यवाही करके निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में शाला में चिकित्सा को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में श्री राघव प्रसाद, श्रीमती चंद्रकला, दिनेश मिश्र, अधिकारी पेटेन, कमार तिपुत्र विजिन आवेदन में सुनवाई के निर्देश दिए। आवेदन परों में सुनवाई की गई। कमिश्नर ने ग्राम रोपर में शासकीय भूमि से बेडखल किए गए परिवारों के आवेदन पर संयुक्त कलेक्टर की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। कमिश्नर ने एसटीएम को योगी पर जांच करता तो जारी नार परिषद गोविंदांड ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए आवेदन दिए। कमिश्नर ने संयुक्त रूप से भूमि और नारी के लिए आवेदन दिए।

जनसुनवाई में 136 आवेदकों के आवेदनों में की गई सुनवाई



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कलेक्टर के मोहन सभागांव में अमजनता के आवेदन के लिए जनसुनवाई का आयोजन के लिए जनसुनवाई का आयोजन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह उर्जु, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी तथा डिटी कलेक्टर आरके सिंह ने आमजनता 136 आवेदन परों में सुनवाई की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि आवेदन पत्रों का संवेदनशीलता से निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आवेदक को भी आवेदन पत्र में की गई कार्यवाही से अवकाश कराएं। जनसुनवाई में सुनवाई का प्रतिवेदन करके वेकुटुपुर में निवासी नार परिषद वेकुटुपुर की प्रक्रियालय में संबंधित अधिकारी उपरिथ रहे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नायब तहसीलदार वेकुटुपुर के प्रक्रियालय में कार्यवाही के

वृक्षारोपण के महाभियान में हर अधिकारी अनिवार्य रूप से भागीदारी निभाए - कमिश्नर



ई ऑफिस में ऑनबोर्ड न होने वाले कार्यालय प्रमुखों की रुक्की वेनवाड़ि - कमिश्नर

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर कार्यालय के सभागांव में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने टीएल पोंथों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण करने के लिए निर्देश दिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि आवेदन में कार्यवाही के

परिसर तथा कार्यालय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें। जिले के सभी प्रमुख सड़कों के किनारों पर अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण कराएं। सभी नार निगम तथा नारीय निकाय पार्कों एवं अन्य स्थानों पर पौधे रोपित करें। प्रयोगिक भूमियों पर पौधे रोपित करें। प्रयोगिक वाले के लिए जारी आयोजित वेनवाड़ि की जांच कराएं।

परिसर तथा कार्यालय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें। अयुक्त नार सम्पादन तथा संचालक वाले के लिए जारी आयोजित वेनवाड़ि को अनिवार्य रूप से उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें। अयुक्त नार सम्पादन तथा संचालक वाले के लिए जारी आयोजित वेनवाड़ि को अनिवार्य रूप से उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें। अयुक्त नार सम्पादन तथा संचालक वाले के लिए जारी आयोजित वेनवाड़ि को अनिवार्य रूप से उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें। अयुक्त नार सम्पादन तथा संचालक वाले के लिए जारी आयोजित वेनवाड़ि को अनिवार्य रूप से उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त स्थल पर पौधे रोपित करें।

किंतु केंद्रीय परिसरों में उपयुक्त

विचार

कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ रहा आंतरिक राजनीतिक संकट

कर्नाटक कांग्रेस की राजनीति में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर एक आंतरिक राजनीतिक संकट विकसित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है क्या कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा? शिवकुमार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह लेने की बढ़ती अटकलों ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस असहमति, आंतरिक संघर्ष, अनुशासन की कमी और अपने सदस्यों के बीच सत्ता संघर्ष से जूझ रही है, जिससे यह मामला और पेचीदा हो गया है अफवाहें जूर पकड़ रही हैं, मुख्य रूप से इसलिए, क्योंकि जी परमेश्वर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण असंतोष को स्वीकार किया है। जबकि सिद्धारमैया कुछ नुकसान नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, शिवकुमार खेमा खुले तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की पैरवी कर रहा है। उनका दावा है कि यह अगले 3 महीनों के भीतर हो सकता है।

अगले 3 महीने की समय सीमा का कारण दिलचस्प है अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि सत्ता संघर्ष अब सामने आ गय है। इसके अलावा, कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने दाव किया है कि लगभग 100 विधायक नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में हैं, जो शीर्ष पर बदलाव का समर्थन करते हैं। डी.के. ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी की है लेकिन बदलाव की संभावना बनी हुई है। 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में लौटी। चर्चा थी कि दोनों नेता शीर्ष पद के दावेदार हैं हाईकमान ने अढ़ाई साल का रोटेशनल फॉर्मूला पेश किया इसके मताबिक, सिद्धारमैया इस साल नवंबर तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर अढ़ाई साल पूरे कर लेंगे। वह अपने नेतृत्व के 25 साल भी पूरे करेंगे। सिद्धारमैया को प्रशासन में उनके व्यापक अनुभव और ओ.बी.सी. समुदाय से उनके मजबूत समर्थन के लिए जाना जाता है।

साल के अंत में बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ, कांग्रेस नेतृत्व एक महत्वपूर्ण ओ.बी.सी. नेता सिद्धारमैया को परेशान करके स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्सुक है। उनका प्रशासन मुफ्त में सामान देने, मुसलमानों को खुश करने और हिंदू समुदाय को विभाजित करने के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर शिवकुमार को 'मिस्टर-फिक्सिट' के रूप में जाना जाता है और कांग्रेस नेतृत्व ने अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी असंतुष्टि से निपटने में उनका इस्तेमाल किया है।

उन्हें उनके कुशल नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल के साथ-साथ उनके वित्तीय संसाधनों और आंतरिक असंतोष को प्रबंधित करने की क्षमता के लिए महत्व दिया जाता है। दोनों नेताओं के कांग्रेस में अपना योगदान है। संकट के समय पार्टी को उनके ज़रूरत है। डी.के. के अलावा, अन्य उम्मीदवार भी इस पद के लिए होड़ में हैं। इक्षतलगायत समुदाय के मंत्री एम.बी. पाटिल भी शीर्ष पद के लिए इच्छुक हैं। शिवकुमार बोक्कालिंगा समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि करुबा समुदाय से सिद्धारमैया एक महत्वपूर्ण ओ.बी.सी. व्यक्ति हैं। असंतुष्ट गतिविधि से चिंतित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में अपने मंत्रियों को पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की चेतावनी दी, साथ ही कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। शिवकुमार ने सार्वजनिक रूप से कहा “पार्टी और हाईकमान जो चाहेगा वही होगा।” उन्होंने कहा, “मैं पास क्या विकल्प है? मुझे उनके साथ खड़ा होना है और उनका समर्थन करना है।” हालांकि, उनका खेमा ‘डी.के. को सीएम बनाना’ का नारा लगात रहता है। इस बीच, सत्ता में वापसी के अवसर पर नजर गड़ाए भाजपा मध्यावधि चुनाव के भविष्यवाणी कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस सरकार जल्द ही गिर सकती है। सिद्धारमैया ने नेतृत्व परिवर्तन के किसी भी सुझाव को खारिज कर दिया है और कांग्रेस आलाकमान ने भी ऐसी किसी संभावना से इंकार किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा विधायकों और नेताओं के साथ बैठकों के बारे नेतृत्व परिवर्तन के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने की बात कहने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की, “कर्नाटक में मुख्यमंत्री में कोई बदलाव नहीं होगा।

मुनीर के पास सत्ता है मगर जनसमर्थन इमरान के साथ, शहबाज के पास प्रधानमंत्री पद है मगर प्रभाव नहीं



देशों और उत्तरी अमेरिका में बसे हजारों कार्यकर्ता इमरान खान की पार्टी के संदेश- अन्याय, सेंसरशिप और चुराये गये जनादेश के खिलाफ अभियान चलाये हुए हैं। इमरान खान की पार्टी की डिजिटल फंटलाइन तैयार हो चुकी है, जो सरकार के नियंत्रण को चुनाती दे रही है। मुनीर को भले ऐसा लगता हो कि उनकी वैश्विक स्वीकार्यता है लेकिन पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि अच्यूत खान, जियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे सैन्य शासकों को भी अंतरराष्ट्रीय वैधता मिली थी, लेकिन घरेलू आक्रोश ने अंततः

बारिश का कहरः प्रकृति का विक्षोभ या विकास की विफलता ?

ललित गर्ग

बीते कुछ वर्षों में पहाड़ों में बारिश एवं बादल फटना अब डर, कहर और तबाही का पर्याय बन गई है। उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिविकम, और पूर्वोर के अन्य पहाड़ी राज्यों में हर वर्ष मानसून के साथ भयावह भूस्खलन, बादल फटना, पुल बहना और सड़कें टूटना एक आम दृश्य बन गया है। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थागत विफलता, सरकारी निर्माण की लापरवाही और अनियोजित विकास की पोल खोलने वाला यथार्थ है। निश्चय ही हाल के वर्षों में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है और बारिश की तीव्रता बढ़ी है। हर वर्ष जब मानसून की पहली बारिश पहाड़ों को भिगोती है, तो स्थानीय जनजीवन एक नई उमीद के साथ खिल उठता है। खेतों में हरियाली, नदियों में जल, और प्रकृति की शीतलता-मानसून एक उत्सव जैसा लगता है। लेकिन हालिया मानसूनी बारिश और मौसमी विक्षोभ का जुगलबंदी से हिमाचल के कई इलाकों में तबाही का जो भयावह मंजर उभरा, उसे हमें कुदरत के सबक के तौर पर देखना चाहिए। बड़ी संया में लोगों की मौत व लापता होने के साथ ही अरबों रुपये की निजी व सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है।

बजाय टनल या वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे उलट है।

निश्चय हो पूरा दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम के बिंदु तेवर नजर आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में जल-प्रलय सी आपदा का विनाश निश्चय ही भयावह है। वैज्ञानिकों को इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों होई है। इस साल की मानसूनी बारिश में मंडी जिले में बादल फटने की घटनाओं ने बुनियादी ढांचे, घरों, सड़कों और बगीचों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उसने पहाड़ों में विकास के स्वरूप को लेकर फिर नये सिरे से बहस छेड़ दी है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण राजमार्ग भूस्खलन और अतिवृष्टि से बाधित रहे हैं। कांगड़ा घाटी में ऐतिहासिक रेल परिवहन को स्थगित करना पड़ा है। शिमला के पास एक बहुमंजिला इमारत के भरभरा कर गिरने के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने भयभीत किया। जब बारिश आती है, तो केवल इमारतें और सड़कें नहीं ढहतीं, आम लोगों का जीवन भी उजड़ जाता है। लोग रातोंरात बेघर हो जाते हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली-पानी की सुविधाएं बंद हो जाती हैं। प्रशासनिक अमला अकसर घटनास्थल पर देर से पहुँचता है और राहत कार्यों में राजनीतिक रस्साकशी आड़े आ जाती है। राहत कैंपों में भोजन, शौचालय और दवाइयों की भारी कमी रहती है। जब किसी राज्य में बड़ी आपदा आती है, तभी मीडिया और नेताओं की नजर जाती है। हेलिकॉप्टर से निरीक्षण, मुआवजे की घोषणाएं, और 'हम साथ हैं' जैसे बयान आते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम सामान्य होता है, पीड़ितों की सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। लंबे समय तक पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य अधर में लटकते हैं।

निश्चय ही मौसम के मिजाज में तल्खी नजर आ रही है लेकिन इस संकट के मूल में कहीं न कहीं अवैज्ञानिक विकास, खराब आपदा प्रबंधन और निर्माण में पारिस्थितिकीय ज्ञान की उपेक्षा भी निहित है। जिसने इस संकट को और अधिक बढ़ाया है। दरअसल, पानी के प्रवाह के जो प्राकृतिक रास्ते थे, हमने उन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर दी हैं। हमने अपेक्षाकृत नयी हिमालयी पर्वतमालाओं पर इतना भारी-भरकम विकास व निर्माण लाद दिया कि वे इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हैं। निर्माण कार्य में स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला और प्राकृतिक सामग्री का प्रयोग बढ़ाया जाए। भू-सर्वेक्षण और ईआईए को अनिवार्य किया जाए, हर निर्माण से पहले वैज्ञानिक स्तर पर जमीन की जाँच और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हो। बनों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए और जलग्रहण क्षेत्रों को पुनर्स्थापित किया जाए। गाँवों और कस्बों के स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि निर्माण कार्य ज़मीनी ज़रूरतों और जोखियों के अनुसार हो।

हिमालय को केवल भूगोल नहीं, अध्यात्म का स्रोत भी माना जाता है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और घाटियां धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती हैं। जब इन स्थानों पर अंधारुद्धुर्धुर्निर्माण होता है, तो केवल भू-आकृति नहीं, सांस्कृतिक चेतना भी नष्ट होती है। पर्वतीय जीवन में तबाही के पीछे केवल प्रकृति नहीं, हमारी नीति, नियत और विकास का वह मॉडल ज़िम्मेदार है जो केवल तात्कालिक लाभ और मुनाफे पर केंद्रित है। हम पहाड़ों को केवल पर्यटक स्थल या परियोजना-स्थल की दृष्टि से न देखें, बल्कि वहाँ के पर्यावरण, संस्कृति और जीवन पद्धति को समझें और संरक्षण का दायित्व लें। नहीं तो हर बारिश के साथ पहाड़ों से जीवन खिसकता जाएगा और एक दिन यह संकट केवल स्थानीय न रहकर गाईय बन जाएगा। दरअसल, पहाड़ों की सर्वेनंशीलता को देखते हुए नये सिरे से निर्माण के मानक तय करने होंगे। वहाँ दैनिक जल निकासी और बरसाती पानी के प्रवाह के लिये वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करनी होगी। निश्चित रूप से पहाड़ों में लगातार बढ़ती जनसंख्या और बुनियादी ढांचे में पहाड़ की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने की कीमत हम चुका रहे हैं। भविष्य में ऐसी आपदाओं को टालने के लिये अतीत के सबक सीखकर हमें विकास के नये मानक तय करने होंगे। ऐसा लगता है कि किसी का इस पर ध्यान ही नहीं कि यदि बुनियादी ढांचे से जुड़े निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जैसा हादसा मंडी अथवा शिमला में हुआ, वैसे हादसे होते ही रहेंगे और उनका दोष प्रकृति पर मढ़कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाएगी। बात केवल हिमाचल की ही नहीं है, उत्तराखण्ड में भी कुछ स्थानों पर भूस्खलन होने से तीरथयात्री संकट में पड़े हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि हम बार-बार विकसित भारत की बात करें, लेकिन सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी करें और मानक होते हुए भी उनका पालन न करें। इस तरह से तो हम विकसित देश नहीं बन सकते।

भावना की ताकत। फैल्ड मार्शल मुनीर भले ही पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं लेकिन इमरान खान जेल से ही सही, पाकिस्तान के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई को लगातार जीवित रखे हुए हैं। जहां तक यह सबाल कि मुनीर और इमरान खान के बीच दुश्मनी कब से शुरू हुई तो आपको बता दें कि इस संघर्ष की जड़ें 2019 में हैं। असीम मुनीर उस समय दूसरू (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) के प्रमुख थे। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके करीबियों की भ्रष्टगतिविधियों के बारे में रिपोर्ट दी थी। इनमें इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के करीबी फ़राह गोगी और अन्य सहयोगियों का नाम सामने आया था। यह रिपोर्ट इमरान खान को अप्रिय लगी और परिणामस्वरूप मुनीर का प्रमुख के पद से असामान्य रूप से शीघ्र तबादला कर दिया गया था। उन्हें केवल आठ महीने में ही हटा दिया गया था जो प्रमुख के लिए असाधारण रूप से छोटा कार्यकाल था। यह वही क्षण था जब इमरान और असीम के बीच व्यक्तिगत खटास की शुरूआत हुई थी। इसके बाद अप्रैल 2022 में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाया गया। इस प्रक्रिया में सेना की भूमिका को लेकर गहन संदेह और नाराज़गी उभरी। इमरान और उनकी पार्टी ने खुलेआम सेना को न्यूटून कहकर तंज कसे और आर्मी नेतृत्व को सत्ता परिवर्तन का दोषी ठहराया। जब असीम मुनीर को नवंबर 2022 में पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया था तब यह स्पष्ट हो गया कि सेना अब इमरान के खिलाफ पूरी तरह से संगठित हो चुकी है। मुनीर की नियुक्ति को इमरान की राजनीतिक वापसी की राह में सबसे बड़ी दीवार माना गया था। इमरान खान ने असीम मुनीर की नियुक्ति के बाद सेना और खिलाफ खुलेआम बोलना शुरू कर दिया था। उन्होंने बार-बार कहा कि मुख्य अपराधी रावलपंडी में बैठा है, जो मुनीर की ओर इशारा था। मई 2023 में जब इमरान को गिरफ्तार किया गया था और पूरे पाकिस्तान में हिंसा और प्रदर्शन भड़के थे तब पीटीआई के खिलाफ भीषण दमन अभियान शुरू हुआ था। हजारों कार्यकर्ता जेलों में डाले गए, कई नेता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए और मीडिया में इमरान की छवि को नुक़सान पहुँचाने की कोशिश की गई थी।

